Economic Times December 11, 2017

Govt Must Accord Top Priority to Agriculture in Budget: Assocham

New Delhi: The government needs to accord top priority to agriculture in the budget as a major shortfall in kharif production resulted in sluggish growth of farm sector in the second quarter this fiscal, Assocham said on Sunday.

While the year-to-year agriculture GVA (Gross Value Addition) growth for the July-September quarter of 2017-18 dropped to 1.7% from 4.1%, measured on basic prices, the fall looks quite sharp at current prices from 10% to 3.7%. —PTI

The Statesman December 11, 2017

Assocham for focus on agriculture

NEW DELHI, 10 DECEMBER

The government needs to accord top priority to agriculture in the Budget as a major shortfall in kharif production resulted in sluggish growth of the farm sector in the second quarter this fiscal, Assocham said today.

While the year-to-year agriculture GVA growth for the July-September quarter of 2017-18 dropped to 1.7 per cent from 4.1 per cent, measured on basic prices, the fall looks quite sharp at current prices from 10 per cent to 3.7 per cent.

It is attributed to a decline in foodgrain production by 2.8 per cent in the second quarter of the current fiscal from a handsome growth of 10.7 per cent in the similar period of 2016-17.

The chamber observed that the shortfall in the second leg of the monsoon seems to have impacted the kharif production. PTI

Financial Express December 11, 2017

New policy: Discoms may shell out ₹18k cr extra

INDUSTRY SOURCES said given the subdued demand for power, financially stretched discoms might not have to evacuate all of the additional electricity to be tied up with new PPAs: At some peak hours, the extra capacity might get utilised, but during longer intervals, it might not.

According to industry sources, discoms need to tie up PPAs for about 30,000 mega watt (MW) of capacity in order for all of them to have "PPAs to cover 100% of requirement" as stated by power minister RK Singh in an event held by Assocham in late October.

Discoms have to pay 'fixed charges' as per the PPAs to recover the costs of establishing and operating a power plant. The annual fixed charge usually amounts to about 10% of the installation cost of the power plant. Going by the industry estimate of ₹6 crore/MW as an installation cost, the fixed capacity charge for 30,000 MW comes to around ₹18,000 crore a year. The average national power purchase cost is ₹3.48 unit.

Discoms spent ₹4.15 lakh crore in purchasing electricity in FY16, which was about 76% of their total expenditure.

To improve the discoms' health, the Uday scheme intends to minimise the gap between power supply cost and revenue earned; the gap has reduced to 42 paise/unit now from 58 paise in FY15.

The situation can be graver for discoms in the contemporary scenario where the country's installed generation capacity is twice its peak demand. This calls for discoms to occasionally back down from evacuating power from contracted capacities when requirements are low. In FY16, Punjab backed down from evacuating power from 3,457 MW, or 27% of its contracted capacity, ending up paying ₹3,000 crore to power plants operated by companies such as GVK Energy, L&T Power Development's NPL and Vedanta.

Power demand is always dynamic depending on seasonal consumption factors. For example, peak power demand in Uttar Pradesh and Gujarat was 20,007 MW and 15,476 MW in September, respectively, while the figures were up to 17,966 MW and 16,566 MW in October.

Currently, states buy power through bilateral arrangements and from the electricity exchanges at spot market rates to cater to power requirements beyond PPA capacities. More than 4,630 million units (MUs) of power were traded through the power exchanges in October. An industry expert, who did not wish to be named, said the idea is also against the "economic wisdom" of increasing competition in the power sector, as it may deter states from trading power at the energy exchanges.

Will 100% PPA policy help stranded power plants? Research firm Icra noted that only 1,400 MW capacity was tied up through long-term PPAs over the past three years. About 20,000 MW of private coal-based power plants in the country do not have any PPAs. However, even if additional 30,000 MW of PPAs are signed through this scheme, it does not guarantee any improvement in plant load factor (PLF) of the coal power plants. Generation capacities would remain unutilised when electricity loads are not high, perpetuating the low-PLF scenario.

Rajasthan Patrika December 11, 2017

एसोचैम ने कहा...

बजट में कृषि पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

नई दिल्ली. अगर किसी एक क्षेत्र को सबसे ज्यादा सरकारी मदद की जरूरत है, तो वह कृषि क्षेत्र है, जिसे आगामी बजट में सर्वोच्च प्राथमिकता देने की जरूरत है। कृषि के क्षेत्र में खरीफ के उत्पादन में बड़ी गिरावट देखी जा रही है, जिसके कारण चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के प्रदर्शन में कृषि क्षेत्र की रफ्तार में गिरावट दर्ज की गई। एसोचैम ने रविवार को यह बातें कही।

एसोचैम ने कहा कि वित्त वर्ष

2017-18 की जुलाई-सितंबर तिमाही में कृषि का जीवीए (सकल मूल्य वृद्धि) 4.1 फीसदी से गिरकर 1.7 फीसदी रहा। इसकी गणना मूल कीमतों के आधार पर की जाती है। मौजूदा कीमतों में गिरावट 10 फीसदी से घटकर 3.7 फीसदी पर आ गई है। इस वजह से चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में खाद्यान्न उत्पादन में तेज गिरावट आई। यह 2.8 फीसदी रही।

Dainik Bhaskar December 11, 2017

कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दे सरकार : एसोचैम

नई दिल्ली| सरकार को बजट में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि खरीफ फसलों के उत्पादन में भारी गिरावट से चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र की वृद्धि कम हो गई है। उद्योग एवं वाणिज्य संगठन एसोचैम ने यह बात कही।उसने कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन की वृद्धि दर पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 4.1 फीसदी की तुलना में कम होकर 1.7 फीसदी रह गई है। आधारभूत कीमत के आधार पर वृद्धि इस दौरान 10 फीसदी से कम होकर 3.7 फीसदी रह गई। इस दौरान खाद्यान्न उत्पादन में 2.8 फीसदी की गिरावट आई और क्षेत्र की वृद्धि कम करने में इसका योगदान रहा। पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में खाद्यान्न उत्पादन में 10.7 फीसदी की वृद्धि हुई थी।

ASSOCHAM IN THE NEWS

Deshbandhu **December 11, 2017**

जीडीपी वृद्धि के बीच कृषि संकट पर ध्यान देने की जरूरत : एसोचैम

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर (एजेंसियां)। अगर किसी एक क्षेत्र को सबसे ज्यादा सरकारी मदद की जरूरत है, तो वह कृषि क्षेत्र है, जिसे आगामी बजट में सर्वोच्च प्राथमिकता देने की जरूरत है। कृषि के क्षेत्र में खरीफ के उत्पादन में बड़ी गिरावट देखी जा रही है, जिसके कारण चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के प्रदर्शन में कृषि क्षेत्र की रफ्तार में गिरावट दर्ज की गई। एसोचैम ने रविवार को यह बातें कहीं। एसोचैम ने कहा कि साल-दर-साल आधार पर वित्त वर्ष 2017-18 की जुलाई-सितम्बर तिमाही में कृषि का जीवीए (सकल मूल्य वृद्धि) 4.1 फीसदी से गिरकर 1.7 फीसदी रहा। इसकी गणना मूल कीमतों के आधार पर की जाती है। मौजूदा कीमतों में गिरावट 10 फीसदी से घटकर 3.7 फीसदी पर आ गई है। इसके कारण चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में खाद्यान्न उत्पादन में तेज गिरावट दर्ज की गई और यह 2.8 फीसदी रही, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 की समान अवधि में यह 10.7 फीसदी पर थी। एसोचैम ने कहा, निश्चित रूप से, खरीफ उत्पादन में इस गिरावट पर मानसून के दूसरे चरण में हुई कम बारिश का भी असर रहा है। कई कृषि वस्तुओं के मूल्य में संकट के कारण भी प्राप्तियों में कमी देखी गई है, जैसा कि वर्तमान कीमतों पर वृद्धि दर में गिरावट देखी जा रही है। चेंबर के महासचिव डीएस. रावत ने कहा कि कृषि क्षेत्र का आधे से ज्यादा जीवीए में पशुधन, मछली पालन और वानिकी का योगदान है। इसलिए वित्त मंत्री अरुण जेटली को विशेष रूप से अर्थव्यवस्था के इन क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए, साथ ही कृषि अवसंरचना जैसे सिंचाई पर भी जोर देना चाहिए।

हमारी बड़ी आबादी को ग्रामीण इलाकों में रोजगार प्राप्त है, भारत का उपभोग आधारित विकास और निवेश तब तक अधूरा है, जब तक कि समूचे कृषि क्षेत्र को संकट से नहीं उबारा जाता है। भारतीय कारोबारी जगत का प्रमुख हिस्सा मुख्य रूप से कृषि मांग पर निर्भर है, अगर तुरंत अल्पकालिक और दीर्घकालिक कदम नहीं उठाए गए तो कृषि मांग में कमजोरी बरकरार रहेगी।

कृषि के क्षेत्र में खरीफ के उत्पादन में देखी जा रही है बड़ी गिरावट

कृषि क्षेत्र का आधे से ज्यादा जीवीए में पशुधन, मछली पालन और वानिकी का योगदान है। इसलिए वित्त मंत्री अरुण जेटली को विशेष रूप से अर्थव्यवस्था के इन क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए।
डीएस. रावत, एसोचैम

Pioneer (Hindi)

December 11, 2017

बजट में कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे सरकारः एसोचैम

एजेंसी। नई दिल्ली

सरकार को बजट में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि खरीफ फसलों के उत्पादन में भारी गिरावट से चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र की वृद्धि कम हो गई है। उद्योग एवं वाणिज्य संगठन एसोचैम ने रविवार को यह बात कही।

उसने कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन की वृद्धि दर पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 4.1 प्रतिशत की तुलना में कम होकर 1.7 प्रतिशत पर आ गई है। आधारभूत कीमत के आधार पर वृद्धि इस दौरान 10 प्रतिशत से कम होकर 3.7 प्रतिशत पर आ गई। इस दौरान खाद्यान्न उत्पादन में 2.8 प्रतिशत की गिरावट आई और क्षेत्र की वृद्धि कम करने में इसका योगदान रहा। पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में खाद्यान्न उत्पादन में 10.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। एसोचैम के महासचिव डी.एस.रावत ने कहा, चूंकि कृषि क्षेत्र में सकल मूल्यवर्धन में पशुपालन, मत्स्यपालन और वानिकी का करीब आधा योगदान होता है, वित्त मंत्री वरुण जेटली को सिंचाई जैसी प्रमुख कृषि ढांचगत संरचना समेत इन क्षेत्रों पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पाता है, उपभोग और निवेश आधारित वृद्धि का तब तक फायदा नहीं होगा जब तक कि पूरे कृषि क्षेत्र को संकट से बाहर नहीं निकाला जाए। उन्होंने आगे कहा, भारतीय उद्योग जगत का बड़ा हिस्सा ग्रामीण मांग पर काफी निर्भर करता है। यह मांग तब तक कम रहेगी जब तक कि अल्पावधि या मध्यावधि में तत्काल इस बाबत कदम नहीं उठाया जाएगा।